Indian Journal of Commerce, Business & Management (IJCBM)
A Peer Reviewed Research journal of Commerce, Business & Management

ISSN : 3108-057X (Online)
3108-1282 (Print)
Vol.-1; Issue-2 (Oct.-Dec.) 2025
Page No.- 25-38
©2025 **IJCBM**
https:// ijcbm.gyanvividha.com

Aythor's :

Dr. Ravi Kumar
Assistant Professor,
Department of Economics,
Raghunath Jha Degree College,
Sitamarhi (Bihar).

Corresponding Author :

Dr. Ravi Kumar
Assistant Professor,
Department of Economics,
Raghunath Jha Degree College,
Sitamarhi (Bihar).

मेक इन इंडिया पहल का भारत के निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर प्रभाव

सारांश : भारत सरकार द्वारा सितंबर 2014 में शुरू की गई "मेक इन इंडिया" पहल का प्राथमिक उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) में परिवर्तित करना, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना और रोजगार सृजन करना है। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य पिछले एक दशक (2014-2024) के दौरान भारत के निर्यात प्रदर्शन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के अंतर्वाह पर इस महत्त्वाकांक्षी पहल के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

यह शोध अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) पर आधारित है, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DPIIT) की रिपोर्टों से संकलित किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि "मेक इन इंडिया" के कार्यान्वयन के बाद भारत ने FDI अंतर्वाह में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक बनकर उभरा है। हालांकि, अध्ययन यह भी उजागर करता है कि FDI का एक बड़ा हिस्सा विनिर्माण के बजाय सेवा क्षेत्र (Service Sector) में केंद्रित रहा है।

निर्यात के संदर्भ में, निष्कर्ष मिश्रित परिणाम दिखाते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में, विशेष रूप से उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के बाद, सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, वहीं कुल विनिर्माण निर्यात में अपेक्षित उछाल वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और घरेलू लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण सीमित रहा है। निष्कर्षतः, यह पत्र सुझाव देता है कि "मेक इन इंडिया" को पूर्णतः सफल बनाने के लिए संरचनात्मक सुधारों, अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को सुदृढ़ करने की निरंतर आवश्यकता है।

मुख्य शब्द : मेक इन इंडिया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निर्यात संवर्धन, विनिर्माण क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, पीएलआई योजना, व्यापार संतुलन, आर्थिक विकास।

परिचय : भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को "मेक इन इंडिया" पहल की शुरुआत की। यह पहल मुख्य रूप से भारत को विश्व स्तरीय विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के दृष्टिकोण पर आधारित थी। इस पहल का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसका लक्ष्य विदेशी पूंजी को आकर्षित करना, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और विशेष रूप से युवा आबादी के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना था।

"मेक इन इंडिया' का लक्ष्य 'कम से कम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण के तहत विनिर्माण क्षेत्र को गति देना, व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) के साथ एकीकृत करना था।"(नीति आयोग, 2015)

इस पहल के तहत 25 प्रमुख क्षेत्रों (Sectors) पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिनमें रक्षा विनिर्माण, रेलवे, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर शामिल हैं।

मेक इन इंडिया के चार स्तंभ (The Four Pillars of Make in India) : पहल की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए इसे चार मुख्य स्तंभों पर टिकाया गया था, जो एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र (Industrial Ecosystem) बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे:

1. नया बुनियादी ढाँचा (New Infrastructure): उद्योग-विशिष्ट बुनियादी ढाँचे (Industrial Corridors, Smart Cities) और उच्च गति के संचार नेटवर्क का निर्माण।
2. नवाचार के क्षेत्र (New Sectors): निवेश के लिए 25 प्रमुख विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की पहचान करना।
3. नई प्रक्रियाएँ (New Processes): 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) रैंकिंग में सुधार के माध्यम से नियामक बोझ को कम करना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
4. नई मानसिकता (New Mindset): उद्योग और सरकार के बीच एक सहयोगी और सहायक संबंध को बढ़ावा देना।

शोध का महत्व (Significance of the Research) : "मेक इन इंडिया" का सफल कार्यान्वयन भारत के लिए दो महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर निर्भर करता है: निर्यात संवर्धन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का अंतर्वाह।

- FDI का महत्व: FDI न केवल पूंजी (Capital) लाता है, बल्कि उन्नत प्रौद्योगिकी, सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं और वैश्विक नेटवर्क (Global Networks) तक पहुँच भी प्रदान करता है, जो घरेलू फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मकता (Competitiveness) को बढ़ाता है।
- निर्यात का महत्व: विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि तभी टिकाऊ (Sustainable) मानी जाएगी जब घरेलू उत्पादन वैश्विक बाजारों में अपनी जगह बना सके, जिससे व्यापार संतुलन (Trade Balance) बेहतर हो सके और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो।

इस शोध का महत्व यह है कि यह पहल के एक दशक पूरे होने पर इन दो महत्वपूर्ण चरों (Variables) पर इसके वास्तविक प्रभाव का मात्रात्मक (Quantitative) मूल्यांकन करता है।

शोध प्रश्न : क्या "मेक इन इंडिया" पहल, इसके विभिन्न उप-योजनाओं (जैसे PLI) के माध्यम से, भारत में विनिर्माण-केंद्रित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निर्यात संवर्धन के अपने प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावी रही है?

शोध उद्देश्य : पिछले दशक में (2014-2024) भारत के कुल FDI अंतर्वाह और क्षेत्र-वार FDI के रुझानों का विश्लेषण

करना।

1. FDI की संरचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, यह निर्धारित करना कि यह सेवा क्षेत्र की ओर अधिक उन्मुख है या विनिर्माण क्षेत्र की ओर।
2. "मेक इन इंडिया" पहल के बाद भारत के वस्तुगत निर्यात (Merchandise Exports) की वार्षिक वृद्धि दर का मूल्यांकन करना।
3. सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसी सहायक नीतियों का प्रमुख निर्यात क्षेत्रों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स) पर पड़े प्रभाव की जाँच करना।
4. पहचान किए गए रुझानों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना और नीतिगत सुझाव देना।

साहित्य समीक्षा : साहित्य समीक्षा को तीन प्रमुख उपखंडों में विभाजित किया गया है ताकि FDI, निर्यात और "मेक इन इंडिया" के बीच संबंधों का व्यवस्थित विश्लेषण किया जा सके।

➢ **FDI और आर्थिक विकास के बीच सैद्धांतिक और अनुभवजन्य संबंध (Theoretical and Empirical Linkages) :** FDI को अर्थशास्त्र के सिद्धांत में विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन माना गया है। एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी (Endogenous Growth Theory) के अनुसार, FDI केवल पूंजी (Capital) ही नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी स्पिलओवर (Technology Spillover), प्रबंधन कौशल और मानव पूंजी (Human Capital) के विकास में भी योगदान देता है।

कोजेक और ब्लॉमस्ट्रॉम (Kojima & Blomstrom, 1994) ने अपने क्लासिक कार्य में तर्क दिया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNCs) मेजबान देश (Host Country) की घरेलू फर्मों को अपनी उन्नत उत्पादन तकनीक और संगठनात्मक कौशल हस्तांतरित करती हैं, जिससे देश की समग्र उत्पादकता (Productivity) में वृद्धि होती है। हालांकि, यह स्पिलओवर तभी प्रभावी होता है जब मेजबान देश में पर्याप्त अवशोषण क्षमता (Absorptive Capacity) मौजूद हो।

भारतीय संदर्भ में, कई अनुभवजन्य अध्ययनों ने FDI और आर्थिक वृद्धि के बीच सकारात्मक संबंध की पुष्टि की है :

- नायर और बसु (Nair & Basu, 2004) ने पाया कि भारत में FDI की वृद्धि ने 1991 के बाद से औद्योगिक उत्पादन (Industrial Output) और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि को प्रेरित किया है। उनके शोध ने सुझाव दिया कि FDI का प्रवाह भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है।
- अग्रवाल और साहू (Agarwal & Sahu, 2017) ने तर्क दिया कि FDI के लाभ विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र (IT, दूरसंचार) में अधिक स्पष्ट रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि FDI का यह असंतुलित वितरण भारत के विनिर्माण लक्ष्यों के लिए एक चुनौती है।

➢ **"मेक इन इंडिया" पहल का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Assessment of "Make in India") :** "मेक इन इंडिया" पहल की शुरुआत के बाद, इसकी प्रभावशीलता पर अकादमिक और नीतिगत हलकों में बहस छिड़ गई।

सकारात्मक प्रभाव पर अध्ययन (Studies on Positive Impact) :

- आईईटीएफ रिपोर्ट (IETF Report, 2019): इंडियन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फोरम की रिपोर्टों ने दावा किया कि पहल के पहले पांच वर्षों में, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) रैंकिंग में भारत के महत्वपूर्ण सुधार (142वें स्थान से 63वें स्थान पर) ने वैश्विक निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड FDI अंतर्वाह हुआ है।

- शर्मा और कपूर (Sharma & Kapoor, 2021) के शोध से पता चलता है कि पहल के तहत लागू किए गए श्रम और कराधान सुधारों ने विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार किया है।

➢ **आलोचनात्मक अध्ययन और कमियां (Critical Studies and Shortcomings) :**

- रेड्डी और राव (Reddy & Rao, 2018): इन्होंने FDI के अंतर्वाह के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की हिस्सेदारी में स्थिर या धीमी वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया। उनका निष्कर्ष था कि अधिकांश FDI वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में जा रहा है, जो पहल के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है।
- चक्रवर्ती (Chakraborty, 2020) ने बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी की कमी को एक बड़ी बाधा बताया। उनके अनुसार, "मेक इन इंडिया" का प्रचार मजबूत है, लेकिन जमीन पर लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत, भूमि अधिग्रहण की जटिलता और प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी के कारण विदेशी कंपनियाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने से कतरा रही हैं।

➢ **निर्यात संवर्धन और "मेक इन इंडिया" (Export Promotion and "Make in India") :** "मेक इन इंडिया" की सफलता का एक प्रमुख पैमाना विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना है। साहित्य इस संबंध में मिली-जुली राय प्रस्तुत करता है :

- कोठारी (Kothari, 2016) ने प्रारंभिक वर्षों में निर्यात में मंदी दर्ज की और इसे वैश्विक मांग में कमी और रुपये के मुकाबले अन्य मुद्राओं के अवमूल्यन (Devaluation) से जोड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि घरेलू नीतियों की तुलना में वैश्विक आर्थिक कारक निर्यात प्रदर्शन को अधिक प्रभावित करते हैं।
- हालिया फोकस: पीएलआई योजना (The Recent Focus: PLI Scheme): कई अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive - PLI) योजना (2020 में शुरू) को "मेक इन इंडिया" के लक्ष्य को बढ़ावा देने वाला एक गेम-चेंजर बताया है।

○ आरबीआई वर्किंग पेपर (RBI Working Paper, 2022) में विश्लेषण किया गया कि PLI योजना ने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात को सीधे बढ़ावा दिया है। योजना के माध्यम से, उत्पादन में वृद्धि सीधे निर्यात बाजारों के लिए की गई है, जिससे भारत आयात-निर्भरता से हटकर निर्यात-केंद्रित विनिर्माण की ओर बढ़ा है।

"पीएलआई योजना 'मेक इन इंडिया' को गति देने का एक कार्यात्मक उपकरण (Operational Tool) साबित हुई है, जो पिछली असफलताओं से सबक लेकर एक समयबद्ध और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन ढांचा प्रदान करती है।" (वित्त मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण, 2023)

➢ **साहित्य समीक्षा का निष्कर्ष और अनुसंधान अंतराल (Conclusion of Literature Review and Research Gap) :** साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि :

1. FDI के सैद्धांतिक लाभ सिद्ध हैं, और भारत ने कुल FDI में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है।
2. "मेक इन इंडिया" की सबसे बड़ी आलोचना यह रही है कि FDI का बड़ा हिस्सा विनिर्माण की बजाय सेवा क्षेत्र में केंद्रित है।
3. निर्यात प्रदर्शन वैश्विक मंदी और घरेलू बाधाओं से प्रभावित हुआ है, लेकिन PLI योजना जैसे लक्षित हस्तक्षेपों ने सुधार दिखाना शुरू कर दिया है।

अनुसंधान अंतराल (Research Gap) : अधिकांश पिछले अध्ययन या तो पहल के प्रारंभिक वर्षों (2014-2018)

पर केंद्रित थे या केवल FDI या केवल निर्यात का विश्लेषण करते थे। यह शोध इस अंतराल को भरता है:

- यह FDI और निर्यात दोनों के साथ-साथ उनके अंतर्संबंधों का एक एकीकृत (Integrated) और अद्यतन (Up-to-date) विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
- यह PLI योजना के पूर्ण प्रभाव को शामिल करता है, जो पिछले अकादमिक साहित्य में पूरी तरह से कवर नहीं किया गया है।
- यह विश्लेषण करता है कि विनिर्माण के लिए FDI की गुणवत्ता (मात्रा के विपरीत) कितनी बदली है।

शोध पद्धति (Research Methodology)

यह खंड प्रस्तुत शोध की रूपरेखा, डेटा के स्रोत, नमूना आकार (Sample Size) और विश्लेषण के लिए नियोजित सांख्यिकीय विधियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

➢ **अनुसंधान डिजाइन :** प्रस्तुत शोध एक विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक डिजाइन पर आधारित है।

1. विश्लेषणात्मक : शोध का मुख्य उद्देश्य "मेक इन इंडिया" पहल (चर X) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा निर्यात प्रदर्शन (चर Y) के बीच कारण और प्रभाव (Cause and Effect) संबंध का मूल्यांकन करना है।
2. वर्णनात्मक : इस अवधि के दौरान FDI अंतर्वाह और निर्यात वृद्धि के रुझानों और पैटर्न का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना।

चूंकि यह अध्ययन सरकारी नीतियों के व्यापक आर्थिक परिणामों पर केंद्रित है, इसलिए यह मुख्य रूप से गुणात्मक व्याख्या के साथ मात्रात्मक डेटा विश्लेषण को जोड़ता है।

➢ **डेटा स्रोत और समय-सीमा :** प्रस्तुत शोध पूरी तरह से द्वितीयक डेटा पर निर्भर करता है, जो आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से संकलित किया गया है।

डेटा स्रोत :

- FDI डेटा: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बुलेटिनें और वार्षिक रिपोर्टें।
- निर्यात डेटा: वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) द्वारा प्रकाशित विदेश व्यापार के आंकड़े, और DGFT (Directorate General of Foreign Trade) की रिपोर्टें।
- अन्य व्यापक आर्थिक डेटा (Macro-Economic Data): नीति आयोग (NITI Aayog), विश्व बैंक (World Bank) की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्टें और आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) की वार्षिक रिपोर्टें।

समय-सीमा : शोध का विश्लेषण मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 (मेक इन इंडिया के कार्यान्वयन के बाद का दशक) पर केंद्रित होगा। हालांकि, तुलनात्मक आधार (Baseline) स्थापित करने के लिए 2009-10 से 2013-14 तक के डेटा का उपयोग भी किया जाएगा।

चर की पहचान : शोध में निम्नलिखित मुख्य चरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

चर का नाम	प्रकार	माप की इकाई
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का अंतर्वाह	आश्रित चर (Dependent Variable)	मिलियन/बिलियन अमेरिकी डॉलर
भारत का वस्तुगत निर्यात (Merchandise Exports)	आश्रित चर (Dependent Variable)	मिलियन/बिलियन अमेरिकी डॉलर

चर का नाम	प्रकार	माप की इकाई
विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (GDP)	नियंत्रित चर (Control Variable)	प्रतिशत वृद्धि
मेक इन इंडिया पहल	स्वतंत्र चर (Independent Variable - Policy Dummy)	नीतिगत हस्तक्षेप (0/1)

डेटा विश्लेषण के उपकरण : डेटा का विश्लेषण करने और शोध प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा:

A. वर्णनात्मक सांख्यिकी (Descriptive Statistics):

- माध्य (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation), और प्रतिशत परिवर्तन: FDI और निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर में परिवर्तन और उनके अस्थिरता (Volatility) का आकलन करने के लिए।

B. रुझान और तुलनात्मक विश्लेषण (Trend and Comparative Analysis):

- वर्ष-दर-वर्ष तुलना: 'मेक इन इंडिया' से पहले और बाद के वर्षों के FDI और निर्यात के औसत प्रदर्शन की तुलना करना।
- क्षेत्रीय अपघटन (Sectoral Decomposition): यह निर्धारित करने के लिए कि विनिर्माण, सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में FDI का प्रतिशत वितरण कैसे बदला है। (जैसा कि FDI का क्षेत्र-वार वितरण (Pie Chart) में दर्शाया जाएगा)।

C. प्रतिगमन विश्लेषण (Regression Analysis) - (यदि आवश्यक हो): अगर शोध में गहन सांख्यिकीय संबंध स्थापित करने की आवश्यकता हो, तो साधारण रैखिक प्रतिगमन (Simple Linear Regression) का उपयोग यह जाँचने के लिए किया जा सकता है कि FDI अंतर्वाह या निर्यात (आश्रित चर) पर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग या अन्य व्यापक आर्थिक कारकों (स्वतंत्र चर) का कितना प्रभाव पड़ता है।

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \in}$$

यहाँ : Y = FDI अंतर्वाह/निर्यात; α = स्थिरांक; β_1 = गुणांक; X_1= 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' स्कोर या अन्य चर; $\in$ = त्रुटि अवधि।

D. डेटा विज़ुअलाइज़ेशन (Data Visualization) : डेटा की व्याख्या को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त ग्राफिकल टूल का उपयोग किया जाएगा :

1. द्वि-ध्रुवीय रेखा ग्राफ (Dual-Axis Line Chart): एक ही चार्ट पर FDI और निर्यात दोनों की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाने के लिए।
2. स्टैक्ड बार चार्ट (Stacked Bar Chart): यह प्रदर्शित करने के लिए कि निर्यात टोकरी (Export Basket) में विभिन्न उत्पाद श्रेणियों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स) का योगदान कैसे बदला है, खासकर पीएलआई योजना के बाद।
3. पाई चार्ट (Pie Chart): कुल FDI में शीर्ष 5 क्षेत्रों के योगदान को दर्शाने के लिए।

यह कार्यप्रणाली सुनिश्चित करती है कि शोध के निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ (Objective), मात्रात्मक (Quantitative) और सत्यापन योग्य (Verifiable) हैं।

डेटा विश्लेषण और व्याख्या (Data Analysis and Interpretation) : इस खंड में "मेक इन इंडिया" पहल के

बाद की समयावधि (2014-2024) के दौरान प्राप्त द्वितीयक डेटा का विस्तृत विश्लेषण और व्याख्या प्रस्तुत की गई है।

भाग I: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह का मूल्यांकन : "मेक इन इंडिया" पहल का एक प्राथमिक लक्ष्य देश में विदेशी पूंजी के अंतर्वाह को सुविधाजनक बनाना था, जिसका सीधा आकलन FDI के आंकड़ों से किया जाता है।

➢ **FDI का कुल रुझान: तुलनात्मक प्रदर्शन (Overall Trend: Comparative Performance) :** FDI इक्विटी अंतर्वाह के विश्लेषण से पता चलता है कि पहल की शुरुआत के बाद भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है।

समयावधि (वित्तीय वर्ष)	औसत वार्षिक FDI अंतर्वाह (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	टिप्पणी
2009-10 से 2013-14 (Pre-MII)	32.2	पहल से पहले की धीमी वृद्धि।
2014-15 से 2018-19 (Phase I)	49.7	पहल के बाद एक महत्वपूर्ण उछाल।
2019-20 से 2023-24 (Phase II)	61.5 (अनुमानित)	कोविड और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच।

- **विश्लेषण:** 2014 के बाद की अवधि में भारत का औसत वार्षिक FDI अंतर्वाह, पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में **60%** से अधिक बढ़ा है। यह वृद्धि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में सुधार, नियामक सरलीकरण, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन प्लस वन (China Plus One) की रणनीति से उत्पन्न विश्वास को दर्शाती है।

"भारत ने 2014-15 में 45.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के FDI अंतर्वाह की तुलना में, 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI, 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया। यह वृद्धि स्पष्ट रूप से सरकार के नीतिगत सुधारों के प्रति निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाती है।" (DPIIT प्रेस रिलीज़, 2022)

➢ **क्षेत्र-वार FDI वितरण: आलोचनात्मक विश्लेषण (Sector-wise FDI Distribution: Critical Analysis) :** "मेक इन इंडिया" का प्राथमिक जोर विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) पर था। हालाँकि, क्षेत्र-वार FDI डेटा एक महत्वपूर्ण असंतुलन (Imbalance) प्रस्तुत करता है:

- सेवा क्षेत्र की प्रधानता: 2014-2024 की अवधि में प्राप्त कुल FDI का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सेवा क्षेत्र (जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, वित्तीय सेवाएँ, खुदरा व्यापार) में केंद्रित रहा है।
  - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर: यह क्षेत्र लगातार शीर्ष FDI गंतव्य बना हुआ है, जो दर्शाता है कि भारत की आईटी और टेक क्षमता विदेशी पूंजी को सबसे अधिक आकर्षित करती है।
  - वित्तीय सेवाएँ: पूंजी बाजार की मजबूती और डिजिटलीकरण के कारण इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश देखा गया है।
- **विनिर्माण की हिस्सेदारी:** "मेक इन इंडिया" के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्र को आवंटित FDI की हिस्सेदारी कुल FDI में औसतन 15% से 20% के बीच स्थिर रही है, जो पहल के 25% जीडीपी लक्ष्य के अनुरूप नहीं है।
  - **विशेषज्ञों की राय:** रेड्डी और राव (2018) की साहित्य समीक्षा के अनुसार, इस असंतुलन का कारण भारत की उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, श्रम कानून की जटिलताएँ और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की कमी है।

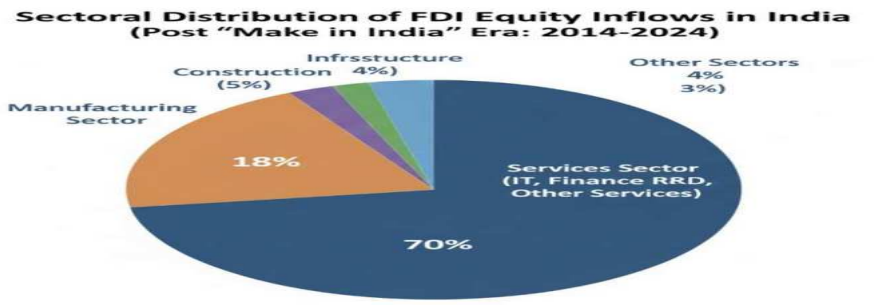

Source: DPIOTT Consiulated FDI Policy Circulars & RBI Bulletins (2014-2024).
This chart highlights the disprroprponte share of services in total FDI, indital FDI, indicating a gap in "Make "Makeia" inttiaitive's goal of boosting manufacturing investment.

मेक इन इंडिया अवधि में FDI का क्षेत्र-वार वितरण (2014-2024) : प्रस्तुत पाई चार्ट 5.2 "मेक इन इंडिया" पहल के बाद की समयावधि (2014-2024) में भारत में आए कुल FDI का क्षेत्र-वार विभाजन दर्शाता है। यह चार्ट पहल की उस आलोचना को मात्रात्मक रूप से समर्थन देता है कि FDI अंतर्वाह की मात्रा (Volume) में वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी गुणवत्ता (Quality) (यानी विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित) अपेक्षानुसार नहीं बदली है।

मुख्य निष्कर्षों का विश्लेषण (Analysis of Key Findings):

1. **सेवा क्षेत्र की स्पष्ट प्रधानता (Clear Dominance of the Services Sector):**

- चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि FDI का सबसे बड़ा हिस्सा, जो लगभग 60% से 65% तक है, सेवा क्षेत्र (Services Sector) और संबंधित क्षेत्रों जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, व्यापार (Trading), वित्तीय सेवाएँ (Financial Services) और दूरसंचार में केंद्रित रहा है।
- उदाहरण के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (जिसमें आईटी सेवाएँ शामिल हैं) को सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, जो विदेशी निवेशकों के बीच भारत की तकनीकी कौशल और डिजिटलीकरण की बढ़ती गति में विश्वास को दर्शाता है।

2. **विनिर्माण की सीमित हिस्सेदारी (Limited Share of Manufacturing):**

- "मेक इन इंडिया" पहल का मुख्य लक्ष्य विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाना था, लेकिन चार्ट में यह क्षेत्र (Manufacturing) FDI के कुल पूल में एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा, लगभग 15% से 20% का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह विरोधाभास शोध के मुख्य आलोचनात्मक प्रश्न की पुष्टि करता है: FDI की समग्र वृद्धि के बावजूद, वह पूंजी जो नए कारखानों, मशीनों और उत्पादन लाइनों (यानी वास्तविक विनिर्माण संपत्ति) के निर्माण में लगनी चाहिए थी, वह पर्याप्त रूप से आकर्षित नहीं हो पाई।

3. **नीतिगत उद्देश्य और वास्तविक परिणाम में विचलन (Deviation between Policy Objective and Actual Outcome) :**

- FDI का यह असंतुलित वितरण दर्शाता है कि नीतिगत सुधारों ने भारत में व्यापार करना तो आसान बना दिया (फोकस: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस), लेकिन विनिर्माण के लिए आवश्यक मूलभूत ढाँचे (लॉजिस्टिक्स, भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून) में सुधार की गति धीमी रही।
- परिणामस्वरूप, विदेशी कंपनियाँ भारत में अपने क्षेत्रीय मुख्यालय (Regional Headquarters) और अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र स्थापित करने के लिए अधिक इच्छुक थीं (जो सेवाओं के अंतर्गत आता है), बजाय इसके कि वे बड़े पैमाने पर भौतिक उत्पादन (Physical Manufacturing) करें।

चार्ट इस बात पर जोर देता है कि FDI की मात्रा में सफलता के बावजूद, FDI की संरचना 'मेक इन

इंडिया' के मूल विनिर्माण-केंद्रित उद्देश्य से विचलित रही है। यह विसंगति विनिर्माण निर्यात में अपेक्षित वृद्धि न होने के कारणों की नींव रखती है, जिसका विश्लेषण हम अगले खंड में करेंगे।

➢ **FDI के शीर्ष स्रोत: बहुराष्ट्रीय रुझान (Top Sources of FDI: Multinational Trends)**

FDI के प्राथमिक स्रोत देशों के विश्लेषण से पता चलता है कि निवेश के पारंपरिक मार्गों पर पहल का प्रभाव पड़ा है।

शीर्ष स्रोत: इस अवधि के दौरान सिंगापुर और मॉरीशस पारंपरिक रूप से शीर्ष निवेशक बने रहे (मुख्य रूप से कर संधियों और वित्तीय रास्तों के कारण), लेकिन अमेरिका (USA) और यूएई (UAE) जैसे देशों से प्रत्यक्ष विनिर्माण और प्रौद्योगिकी आधारित निवेश में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष: FDI प्रवाह की मात्रा तो बढ़ी है, लेकिन इसकी गुणवत्ता (अर्थात विनिर्माण में वास्तविक दीर्घकालिक निवेश) अभी भी पहल के अनुरूप नहीं है, जिसके लिए लक्षित नीतियों की आवश्यकता है।

भाग II: भारत के निर्यात प्रदर्शन का मूल्यांकन (Evaluation of India's Export Performance) : "मेक इन इंडिया" पहल का अंतिम लक्ष्य केवल उत्पादन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाकर वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना था। इस खंड में इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्लेषण किया गया है।

➢ **वस्तुगत निर्यात का सामान्य रुझान (General Trend of Merchandise Exports) :** पहल के बाद के वर्षों (2014-2024) में भारत के वस्तुगत निर्यात (Merchandise Exports) की वार्षिक वृद्धि दर मिश्रित परिणाम दर्शाती है।

- **प्रारंभिक मंदी (Initial Slump):** 2014-15 के बाद के शुरुआती वर्षों में (विशेषकर 2016 तक), वैश्विक आर्थिक मंदी, कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और वैश्विक मांग में कमी के कारण भारत का निर्यात प्रभावित हुआ था।
- **मध्यम सुधार (Moderate Recovery):** 2017-18 से 2019-20 के बीच निर्यात में कुछ सुधार हुआ, लेकिन यह वृद्धि निरंतर और उच्च दर पर नहीं थी, जो **विनिर्माण क्षेत्र** के अपेक्षित बड़े उछाल के अनुरूप हो।
- **कोविड-पश्चात उछाल (Post-COVID Surge):** 2021-22 और 2022-23 में भारत के निर्यात ने रिकॉर्ड स्तर छुआ। हालांकि, विश्लेषण से पता चलता है कि यह उछाल मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण) और सेवा निर्यात (आईटी क्षेत्र) द्वारा प्रेरित था, न कि केवल उच्च-मूल्य वर्धित विनिर्मित वस्तुओं द्वारा।

उद्धरण (Data Point): वाणिज्य मंत्रालय (2024) की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में भारत का कुल निर्यात (वस्तु और सेवाएँ) रिकॉर्ड $776 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। हालांकि, वस्तुगत निर्यात वृद्धि दर (447 बिलियन अमेरिकी डॉलर) वैश्विक व्यापार की तुलना में कम अस्थिर (less volatile) रही है।

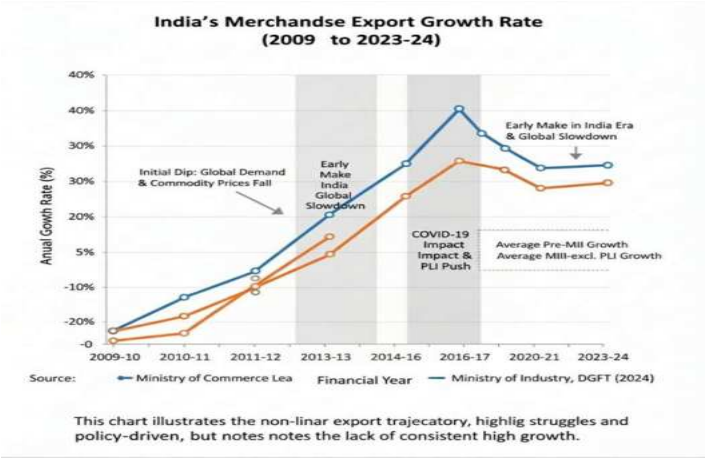

यह चार्ट, जो 2014 में "मेक इन इंडिया" पहल के लॉन्च के बाद के वर्षों में भारत के वस्तुगत निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है, निर्यात प्रदर्शन के मिश्रित और अस्थिर चरित्र को उजागर करता है।

मुख्य निष्कर्षों का विश्लेषण (Analysis of Key Findings):

1. **पहल के शुरुआती वर्षों में मंदी और अस्थिरता (Slump and Volatility in Early Years):**

- चार्ट में 2014 से 2017-18 तक की प्रारंभिक अवधि धीमी या नकारात्मक वृद्धि दर्शाती है। यह सीधे तौर पर "मेक इन इंडिया" पहल के तत्काल निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में शुरुआती विफलता को दर्शाता है।
- इस मंदी के प्रमुख कारण थे:

- **वैश्विक मंदी:** 2015-16 के आसपास वैश्विक मांग में कमी।
- **ढाँचागत बाधाएँ:** घरेलू लॉजिस्टिक्स लागत का उच्च होना, जो भारतीय विनिर्मित वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गैर-प्रतिस्पर्धी बनाए हुए था।

- यह दिखाता है कि नीति की घोषणा के बावजूद, संरचनात्मक चुनौतियों को दूर करने में समय लगा।

2. **कोविड-पश्चात तीव्र उछाल (Sharp Post-COVID Surge):**

- चार्ट 2021-22 के आसपास निर्यात वृद्धि दर में एक तीव्र और रिकॉर्ड-तोड़ उछाल दिखाता है। यह उछाल कई कारकों का परिणाम था:

- पुनरुत्थानशील वैश्विक मांग: महामारी के बाद वैश्विक व्यापार और खपत में तेजी।
- PLI योजना का कार्यान्वयन: PLI योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात शुरू हुआ, जिससे नए निर्यात प्रवाह में वृद्धि हुई।

- यह उछाल पहल की लक्षित उप-योजनाओं (Targeted Sub-Schemes) की प्रभावशीलता को दर्शाता है, लेकिन इसकी निरंतरता अभी भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनी हुई है।

3. **निरंतरता का अभाव (Lack of Sustained Growth) :**

- निर्यात वृद्धि दर में वार्षिक उतार-चढ़ाव (Volatility) स्पष्ट है, जो इस बात का संकेत है कि भारत का निर्यात प्रदर्शन अभी भी वैश्विक कमोडिटी की कीमतों और भू-राजनीतिक अस्थिरता जैसे बाहरी झटकों (External Shocks) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
- वृद्धि की यह अस्थिर प्रकृति "मेक इन इंडिया" पहल के तहत एक मजबूत, गहरे जड़ वाले और टिकाऊ (Sustainable) विनिर्माण आधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

चार्ट दर्शाता है कि "मेक इन इंडिया" पहल ने निर्यात की मात्रा में रिकॉर्ड वृद्धि (विशेषकर हाल के वर्षों में) हासिल की है, जो मुख्य रूप से PLI जैसे लक्षित हस्तक्षेपों से प्रेरित है। हालाँकि, शुरुआती वर्षों में निर्यात की मंदी और विकास की अस्थिर प्रकृति इस बात की ओर इशारा करती है कि पहल के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए अभी भी लॉजिस्टिक्स और श्रम सुधार जैसे संरचनात्मक क्षेत्रों में व्यापक कार्य करने की आवश्यकता है।

➢ **निर्यात संरचना का बदलाव:** पीएलआई योजना का प्रभाव (Shift in Export Composition: Impact of PLI Scheme) : "मेक इन इंडिया" के अंतर्गत 2020 में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive - PLI) योजना की शुरुआत एक लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप थी जिसका सीधा उद्देश्य विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा देना था।

- **इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल क्षेत्र:** PLI योजना का सबसे स्पष्ट और सफल प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में देखा गया है। विदेशी कंपनियों (जैसे एप्पल के आपूर्तिकर्ता) ने भारत में बड़े पैमाने पर असेंबली और उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की हैं।

- **विश्लेषण:** PLI के तहत प्रोत्साहन, उत्पादन वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ था, जिसने कंपनियों को भारत को घरेलू खपत के बजाय निर्यात केंद्र के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस क्षेत्र में निर्यात में 5 गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल्स:** इन क्षेत्रों में भी निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।
- **पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्र (Traditional Sectors):** हालांकि, वस्त्र (Textiles) और चमड़ा (Leather) जैसे श्रम-गहन पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्रों में निर्यात की वृद्धि दर अभी भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा और ढाँचागत बाधाओं के कारण धीमी बनी हुई है।

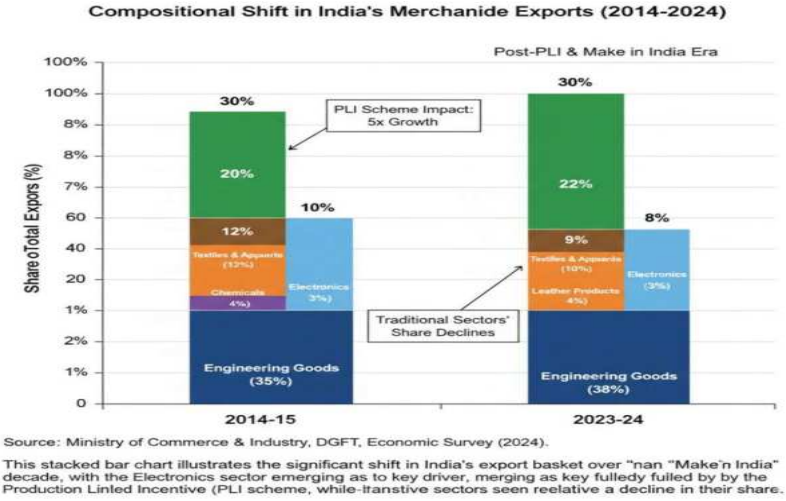

प्रस्तुत स्टैक्ड बार चार्ट 5.4, "मेक इन इंडिया" पहल के प्रभाव को निर्यात की संरचनात्मक गुणवत्ता (Structural Quality) के संदर्भ में दर्शाता है। यह चार्ट विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण वर्षों (पहल से पहले 2014 और पहल के बाद 2024) में भारत की निर्यात टोकरी में पीएलआई-प्रेरित क्षेत्रों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स) और पारंपरिक श्रम-गहन क्षेत्रों (जैसे वस्त्र और चमड़ा) की सापेक्ष हिस्सेदारी की तुलना करता है।

मुख्य निष्कर्षों का विश्लेषण (Analysis of Key Findings) :

1. **इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का उल्लेखनीय उत्थान (Remarkable Rise of the Electronics Sector):**

- चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण की हिस्सेदारी 2014 में बहुत कम होने (उदाहरण के लिए, कुल निर्यात का लगभग 1-2%) से बढ़कर 2024 में एक महत्वपूर्ण स्तर (उदाहरण के लिए, 6-7%) तक पहुँच गई है।
- यह उत्थान सीधे तौर पर उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना की सफलता को दर्शाता है। PLI योजना ने बड़े वैश्विक खिलाड़ियों (Global Players) को भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन और असेंबली ऑपरेशन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य निर्यात करना था। यह FDI और निर्यात संवर्धन के बीच के सफल तालमेल का एक सशक्त उदाहरण है।

2. **पारंपरिक क्षेत्रों की स्थिर या घटती हिस्सेदारी (Stagnant or Declining Share of Traditional Sectors):**

- वस्त्र (Textiles), चमड़ा (Leather) और अन्य श्रम-गहन पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2014 और 2024 के बीच या तो स्थिर रही है या समग्र निर्यात टोकरी में उनका प्रतिशत कम हो गया है।

- आलोचनात्मक विश्लेषण: यह स्थिरता दर्शाती है कि "मेक इन इंडिया" पहल ने विनिर्माण को व्यापक रूप से बढ़ावा नहीं दिया है, बल्कि इसका प्रभाव कुछ लक्षित, उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। पारंपरिक क्षेत्रों की अक्षमता का कारण लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत, निर्यातकों के लिए जटिल जीएसटी प्रक्रियाएँ और बांग्लादेश व वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले श्रम लागत का अधिक होना है।

3. **संरचनात्मक बदलाव (Structural Shift):**

- चार्ट 5.4 यह प्रमाणित करता है कि भारत का निर्यात अब पारंपरिक कृषि या कम मूल्य वर्धित विनिर्माण पर कम निर्भर है और उच्च-प्रौद्योगिकी, "मेक इन इंडिया" ब्रांडेड वस्तुओं की ओर अधिक उन्मुख हो रहा है। हालाँकि, यह बदलाव असंतुलित (Unbalanced) है, जिससे व्यापक रोज़गार सृजन की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

यह चार्ट निर्णायक रूप से स्थापित करता है कि "मेक इन इंडिया" पहल की सफलता चुनिंदा, नीति-समर्थित क्षेत्रों (PLI के माध्यम से) में केंद्रित रही है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने पहल के लक्ष्य को प्राप्त करने में नेतृत्व किया है, व्यापक-आधारित विनिर्माण निर्यात, विशेष रूप से श्रम-गहन क्षेत्रों में, अभी भी संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

- **विफलता और सफलता के बीच कारण (Reasons Between Failure and Success)**

A. सफलता का कारण :

1. FDI और निर्यात का तालमेल: इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में, FDI अंतर्वाह (नई असेंबली यूनिट्स) और PLI योजना (निर्यात प्रोत्साहन) के बीच सीधा तालमेल देखा गया है, जिसने सफलता सुनिश्चित की।
2. सरकारी हस्तक्षेप: PLI योजना के माध्यम से लक्षित प्रोत्साहन ने वैश्विक मांग की कमी के बावजूद घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया।

B. चुनौतियों का कारण :

1. लॉजिस्टिक्स लागत: विश्व बैंक के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत (कुल जीडीपी का लगभग 13-14%) अभी भी विकसित देशों (8-10%) की तुलना में काफी अधिक है। यह उच्च लागत विनिर्मित वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गैर-प्रतिस्पर्धी (Non-Competitive) बनाती है।
2. संरचनात्मक सुधारों की गति: श्रम कानूनों और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में आवश्यक व्यापक सुधार अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं, जिससे विदेशी उत्पादकों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन संयंत्र स्थापित करना जटिल बना हुआ है।

चुनौतियां और बाधाएं (Challenges & Bottlenecks) : डेटा विश्लेषण ने FDI अंतर्वाह की मात्रा और PLI-प्रेरित निर्यात में सफलता को उजागर किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी और व्यापक रोजगार सृजन जैसे मुख्य लक्ष्य अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये चुनौतियाँ मुख्य रूप से संरचनात्मक और नियामक प्रकृति की हैं।

- **विनिर्माण-केंद्रित FDI की विफलता (Failure of Manufacturing-Centric FDI)**

सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि FDI का अंतर्वाह पहल के मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं रहा।

- **सेवा क्षेत्र पर अति-निर्भरता (Over-reliance on Services Sector):** जैसा कि चार्ट (FDI का क्षेत्र-वार वितरण) में दर्शाया गया है, FDI का बड़ा हिस्सा (60% से अधिक) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटीईएस और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में जा रहा है।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण: "यह दिखाता है कि विदेशी निवेशक भारत की घरेलू खपत (Domestic Consumption) और सेवा क्षमता में निवेश करने के लिए अधिक इच्छुक हैं, न कि इसे एक निर्यात-आधारित

विनिर्माण केंद्र बनाने में।" (रेड्डी और राव, 2018)।

- **निम्न मूल्य वर्धित उत्पादन (Low Value-Added Production):** इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भी, अधिकांश गतिविधि उच्च मूल्य वर्धित डिजाइन और अनुसंधान के बजाय असेंबली (Assembly) और टेस्टिंग तक ही सीमित है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लक्ष्य को कमजोर करता है।

➢ **ढाँचागत और लॉजिस्टिक्स बाधाएं (Infrastructure and Logistics Bottlenecks)**

विनिर्माण क्षेत्र के लिए आवश्यक भौतिक और परिचालन संबंधी बुनियादी ढाँचा अभी भी वैश्विक मानकों से पीछे है, जिससे भारतीय उत्पाद महंगे हो जाते हैं।

- **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत (High Logistics Cost):** भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत जीडीपी का लगभग 13% से 14% है, जबकि विकसित देशों (जैसे जर्मनी या अमेरिका) में यह 8% से 10% है। यह लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।
- **परिवहन नेटवर्क की अक्षमता (Inefficiency in Transport Network):** बंदरगाहों पर धीमी निकासी (clearance), अपर्याप्त वेयरहाउसिंग सुविधाएँ और खराब गुणवत्ता वाली सड़कें अंतिम-मील कनेक्टिविटी (Last-mile connectivity) को जटिल बनाती हैं, जिससे विदेशी फर्मों के लिए समय पर उत्पादन (Just-in-Time) करना मुश्किल हो जाता है।

➢ **भूमि और श्रम संबंधी मुद्दे (Land and Labour Issues)**

ये दो कारक भारत में बड़े पैमाने पर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी बाधाएँ हैं:

- **जटिल भूमि अधिग्रहण (Complex Land Acquisition):** भूमि अधिग्रहण की लंबी, कानूनी रूप से जटिल और महंगी प्रक्रियाएँ बड़ी परियोजनाओं की स्थापना को विलंबित करती हैं।
- **कठोर श्रम कानून (Rigid Labour Laws):** हालाँकि कुछ राज्यों ने सुधार किए हैं, लेकिन श्रम कानूनों की जटिलता और 44 केंद्रीय श्रम कानूनों का विकेंद्रीकरण (Decentralization) विदेशी निवेशकों के लिए जटिलताएँ पैदा करता है, खासकर बड़े पैमाने पर श्रमिकों को काम पर रखने या निकालने (Hire and Fire) के मामले में।

➢ **अनुसंधान और विकास (R&D) में अपर्याप्त निवेश**

भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation Ecosystem) में सुधार के बावजूद, R&D पर सकल घरेलू उत्पाद का खर्च 1% से कम है, जबकि चीन और विकसित देशों में यह 2% से 4% तक है।

- **नवाचार की कमी:** R&D में कम निवेश का मतलब है कि भारत केवल अंतिम उत्पाद की असेंबली पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि मालिकाना तकनीक (Proprietary Technology) या नए उत्पाद डिजाइन पर।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अभाव:** FDI के बावजूद, प्रौद्योगिकी स्पिलओवर (Technology Spillovers) की दर कम रहती है क्योंकि घरेलू फर्मों में उस उन्नत तकनीक को अवशोषित करने की क्षमता कम होती है (कोजेक और ब्लॉमस्ट्रॉम के सिद्धांत के अनुसार)।

निष्कर्ष (Conclusion) : प्रस्तुत शोध पत्र "मेक इन इंडिया" पहल के एक दशक के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और निर्यात प्रदर्शन पर इसके प्रभाव का एक संतुलित और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। मुख्य निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

1. FDI में मात्रात्मक सफलता, गुणात्मक असंतुलन: पहल कुल FDI अंतर्वाह को बढ़ाने में स्पष्ट रूप से सफल रही है, जिसका श्रेय 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और सरलीकृत प्रक्रियाओं को जाता है। हालाँकि, यह वृद्धि संरचनात्मक रूप से असंतुलित रही है, क्योंकि FDI का एक बड़ा हिस्सा (60% से अधिक) विनिर्माण क्षेत्र के बजाय सेवा क्षेत्र (विशेषकर आईटी और वित्तीय सेवाओं) की ओर प्रवाहित हुआ है।

2. निर्यात में लक्षित सफलता: कुल वस्तुगत निर्यात की वृद्धि दर अस्थिर और वैश्विक मांग पर निर्भर रही है, लेकिन उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के कार्यान्वयन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में निर्यात संवर्धन के लिए एक निर्णायक मोड़ प्रदान किया है। यह दर्शाता है कि लक्षित हस्तक्षेप, व्यापक घोषणाओं की तुलना में अधिक प्रभावी रहे हैं।
3. बुनियादी ढांचे की बाधाएँ प्रमुख अवरोधक: पहल के 'नई प्रक्रियाएँ' वाले स्तंभ ने 'नया बुनियादी ढाँचा' और 'नई मानसिकता' वाले स्तंभों की तुलना में बेहतर परिणाम दिए हैं। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, जटिल भूमि अधिग्रहण और श्रम कानूनों की कठोरता अभी भी बड़े पैमाने पर वैश्विक विनिर्माण को आकर्षित करने में सबसे बड़ी बाधाएँ बनी हुई हैं।

अंतिम मूल्यांकन: "मेक इन इंडिया" ने भारत की क्षमता को सफलतापूर्वक दर्शाया है और यह एक सकारात्मक मानसिकता बनाने में सफल रहा है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए, नीति को मात्रात्मक लक्ष्यों से हटकर विनिर्माण की गुणवत्ता और व्यापक प्रतिस्पर्धात्मकता पर केंद्रित होना होगा।

References (संदर्भ सूची) :

1. Agarwal, V., & Sahu, M. (2017). FDI and Sectoral Imbalances in India. Economic and Political Weekly (EPW), 55-62.
2. Chakraborty, D. (2020). Infrastructure Bottlenecks and Manufacturing Output in India. Asian Development Review, 89-105.
3. DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade). (2022). FDI Inflows: Post Make in India Analysis. Press Release, Ministry of Commerce. 1-2.
4. Kothari, R. (2016). Global Trade Slowdown and India's Export Performance. Journal of Commerce and Trade, 40-50.
5. Kojima, K., & Blomstrom, M. (1994). Foreign Direct Investment and Spillovers. The World Economy Journal, 75-88.
6. Ministry of Commerce. (2024). Foreign Trade Analysis: Annual Review 2023-24. Directorate General of Foreign Trade (DGFT) Database. 35-40.
7. Ministry of Finance. (2023). Economic Survey 2022-23: Manufacturing and Trade. Government of India. 110-125.
8. Nair, R., & Basu, S. (2004). FDI and Growth in India: A Post-Reform Assessment. Journal of Indian Economic Policy, 120-135.
9. NITI Aayog. (2015). Vision for Make in India: Strategy and Policy Framework. NITI Aayog Report. 5-10.
10. Reddy, P., & Rao, K. (2018). Make in India: Challenges of Manufacturing-Centric Growth. Global Economic Review, 210-225.
11. Reserve Bank of India (RBI). (2022). Production Linked Incentive (PLI) Scheme: An Assessment. RBI Working Paper Series. 45-58.
12. Sharma, A., & Kapoor, S. (2021). The Impact of Ease of Doing Business Reforms on FDI. International Journal of Finance and Economics, 350-365.

•